

CSIR in Media



A Daily News Bulletin
14th to 16th November 2017



NIPER collaborates with CSIR-CDRI for research

CSIR-CDRI

16th November 2017

NIPER has signed an MoU with the CSIR-CDRI (Central Drug Research Institute), Lucknow, for research collaboration and development of pharmaceutical sciences.

The objectives of the programme are to promote institutional linkage between the CSIR-CDRI and NIPER and provide cooperation through collaborative research programs in scientific fields of research. Both institutions will jointly identify specific fields of research and faculty/scientist exchange programmes will be mutually conducted for scientific conferences, workshops symposia, meetings in the areas of drug discovery.

Published in:
[The Tribune](#)

CSIR-CSMCRI

16th November 2017

‘गुजरात वैज्ञानिक साक्षरता महोत्सव’ में सीएसएमसीआरआई ने की भागीदारी

भावनगर

आमजन मानस एवं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने हेतु वलसाड में 26-28, अक्टूबर, 2017 के दौरान ‘गुजरात वैज्ञानिक साक्षरता महोत्सव’ के अंतर्गत बहुआयामी प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एक विज्ञान व प्रौद्योगिकी कार्यशाला सह प्रदर्शनी का सेंटर फॉर साइंस, टेक्नॉलॉजी एंड इन्नोवेशन (सीएसटीआई), नई दिल्ली द्वारा आयोजन किया गया। जिसमें अनुसंधान एवं विकास ज्ञानाधार के लिए विख्यात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो चुके/ रहे शोधों, उत्पादों/ प्रौद्योगिकियों आदि के प्रदर्शन तथा जानकारी देने हेतु आमंत्रित किया गया था। सीएसआईआर का प्रतिनिधित्व कर रही

भावनगर में स्थित सीएसआईआर की प्रयोगशाला-केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीआरआई) ने सम्पूर्ण देश में विविध क्षेत्रों में कार्यरत



सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, कृषि और खाद्य सुरक्षा, दुग्ध उत्पादन, नवीन ऊर्जा स्रोत, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन-

कारण और परिणाम, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे आमजन मानस के कृयाण एवं देश के विकास हेतु हो रहे शोधों व नवाचारों से दर्शनार्थियों एवं विद्यार्थियों को अवगत कराया। सीएसआईआर के वैज्ञानिकों की टीम ने विद्यार्थियों एवं युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभव रोजगार के बारे में जानकारी, कौशल विकास तथा सीएसआईआर द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे अन्य प्रयासों से भी अवगत कराया। ‘नवाचारों एवं प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण विकास में सीएसआईआर की भूमिका’ पर एक व्याख्यान भी दिया गया। महोत्सव में आए विविध स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों/ आगंतुकों/ आम लोगों ने सीएसआईआर के समावेशी आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने हेतु बृहत नवोन्मेषों के प्रति अपनी जिज्ञासा तथा उत्साह दिखाया।

Published in:

Gujrat Vibhav, Page no. 1

CSIR-CBRI

16th November 2017

अनुज, शालिनी व रिया ने जीता स्वर्ण

जागरण संवाददाता, रुड़की : सीएसआइआर केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में आयोजित स्वच्छता पखवाड़े का बुधवार को समापन हो गया। इस मौके पर एक से लेकर 15 नवंबर के मध्य हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

स्वच्छता पखवाड़े के अंतिम दिन बुधवार को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के तहत कक्षा नौ और दस के विद्यार्थियों के लिए स्वच्छता और आरोग्यता विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थी स्वच्छता, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीकी आदि विषयों से संबंधित प्रश्नों से काफी लाभांविता हुए। प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय एक के अनुज, शालिनी और रिया की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। प्रदीप, दीपाली और पारस की टीम द्वितीय रही। जबकि वंशु, पियूष और अभिषेक की टीम तृतीय रही। प्रथम आने वाली टीम को स्वर्ण, द्वितीय को रजत और तृतीय को कांस्य पदक के साथ प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। स्वच्छ संवाद के तहत संस्थान के कार्मिकों के लिए आयोजित निबंध प्रतियोगिता में वैज्ञानिक कौशिक



सीबीआरआई रुड़की में स्वच्छता पखवाड़ा के समापन कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक के साथ विजेता छात्र • जागरण

पंडित प्रथम, राजेश त्यागी द्वितीय और अमन कुमार तृतीय स्थान पर रहे।

संस्थान के निदेशक डा. एन गोपालकृष्णन ने सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया। वहीं विद्यार्थियों ने संस्थान की समग्र प्रयोगशालाओं का दौरा भी किया। संस्थान के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अतुल अग्रवाल ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत संस्थान

में प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों एवं सभी अनुभागों की समग्र स्वच्छता के जरिए सभी को स्वच्छता के महत्व को लेकर जागरूक किया गया।

इस मौके पर शिक्षक आलोक गुप्ता, विनीत सैनी, विनोद कुमार, रश्मि देवी, बीके कालरा, अर्चना, हरीश, विवेक कुशवाहा, पलक गोयल, मेहराजूदीन आदि उपस्थित रहे।

Published in:

Dainik Jagran, Page no. 7

Also published in:

Awam E Hind, Page no.2 , Hindustan, Page no. 6,
Rastriya Sahara, Page no. 4

CSIR-IITR

15th November 2017

हवाई जहाज भी बढ़ा रहे प्रदूषण, होनी चाहिए जांच

आईआईटीआर के निदेशक ने कहा- सीपीसीबी को लखनऊ में लोकेशन बढ़ाने की जरूरत

अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ।

लखनऊ में करीब 80 फ्लाइटों का रोजाना एयरपोर्ट से आना-जाना होता है। दिल्ली में इससे कई गुना अधिक ट्रैफिक है। ये एयरक्राफ्ट प्यूल के रूप में अनलेडेड केरोसिन का उपयोग करते हैं। अपनी उड़ान के

समय शहर के ऊपर बड़ी मात्रा में इनके द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले सूक्ष्म कण छोड़ने की आशंका है। ऐसे में जरूरी है कि वायु प्रदूषण के पीछे इन फ्लाइटों की भी भागीदारी की जांच होनी चाहिए।

लखनऊ में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के पीछे एयर ट्रैफिक के भी एक वजह होने की आशंका दुनिया की प्रमुख वैज्ञानिक संस्था

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (आईआईटीआर) के निदेशक प्रो. आलोक धवन ने जताई है।

प्रो. धवन का कहना है कि अगर फ्लाइट के उड़ान भरने और वायु प्रदूषण में संबंध पता चलेगा तो इससे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी प्रयास किए जा सकेंगे। 30 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले

विमान काफी वायु प्रदूषण पैदा कर सकते हैं जो सीधा हवा में ही मिलेगा।

एयरपोर्ट अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक 2016 में 29,306 विमानों की आवाजाही लखनऊ एयरपोर्ट से हुई। इसमें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ान के लिए छोटे-बड़े दोनों तरह के एयरक्राफ्ट शामिल हैं। वहीं 39 लाख यात्रियों ने लखनऊ एयरपोर्ट का उपयोग किया।

हवा में
घुलता
जहर



हर रोज दमघोंटू हो रही लखनऊ की हवा

पिछले एक महीने के आंकड़े देखें तो एक्यूआई 200 से ऊपर ही रहा। यह स्तर बिगड़ी हवा की श्रेणी में आता है। अब तो यह इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया है जो बेहद खतरनाक है।

एक्यूआई : कब-क्या?

आंकड़ा	हाल	असर
50 से कम	अच्छी	सेहत को नुकसान नहीं
50-100	संतोषजनक	बीमार लोगों को सांस लेने में दिक्कत संभव
100 - 200	बिगड़ी हवा	अस्थमा, दिल के मरीजों के लिए नुकसानदेह
200 - 300	खराब	लंबे समय में सांस का मरीज बना सकती
300 - 400	बहुत खराब	सांस की दिक्कत और लंबे समय में दूसरी बीमारियां
400 से अधिक	खतरनाक	सेहतमंद लोगों को भी बीमार बना सकता

सीपीसीबी की सिर्फ
तीन लोकेशन

प्रो. धवन का कहना है कि 450 वर्ग किमी में फैल चुके लखनऊ का केवल तीन लोकेशन से वायु प्रदूषण आंकना ठीक नहीं है। ऐसे में सीपीसीबी को अपनी लोकेशन की संख्या बढ़ानी चाहिए। इसके लिए उन्हें पत्र भी लिखा गया। अगर सीपीसीबी लोकेशन पर साइट विकसित कर दे तो ऐसे में आईआईटीआर सभी साइटों की निगरानी करा लेगा। हमें बजट दिया तो हमारी टीम साइट लगाने का काम भी करा देगी।

पता करें, कहां से
हो रहा प्रदूषण

प्रो. धवन का कहना है कि अभी मध्य पूर्व से हवा के साथ कणों के आने की सूचना मिली है। ऐसा संभव भी है। लंदन में अभी पिछले दिनों लाल सूर्य की घटना यूरोप और अफ्रीका के देशों से आए धूल के कणों ने कराई थी। हमें भी अपनी हवा में मौजूद कणों की जांच कर इसे सुनिश्चित करना होगा। इससे दूसरे देशों की मदद लेकर वायु प्रदूषण से निपटा जा सकता है।

इन पर भी लगाया जाए अंकुश

- >> मेट्रो के कामों में डीजल का अंधाधुंध उपयोग
- >> शहर में वाहनों की संख्या
- >> मनमाने तरीके से निर्माण कार्य
- >> खुले में डाली गई निर्माण सामग्री हटे
- >> प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों या दूसरे उपकरणों पर पाबंदी लगे

कूड़ा जलाने पर कटा पांच का वेतन



लखनऊ। नगर निगम कर्मचारी चेतावनी दिए जाने के बाद भी कूड़ा जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को ऐसे पांच कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कूड़ा जलाते पाए जाने पर उनका एक दिन का वेतन काट दिया गया है। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक पंकज शुक्ला ने बताया कि निरीक्षण के समय अमीनाबाद में सफाई कर्मचारी पूनम, हरी, मनोरमा, राजरानी और मेवालाल कूड़ा जलाते पाए गए। इनका एक दिन का वेतन काटा गया है।

हाईकोर्ट ने 9 नवंबर 2016 के आदेश में कहा था

- >> राजनीतिक रैलियों के आयोजन के दौरान अगर बाहर की गाड़ियां लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में लाई गईं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
- >> राजधानी में जारी निर्माण कार्यों के तहत पथरों की कटाई तत्काल रोक दी जाए।
- >> लखनऊ में किसी भी पेड़ को काटने पर पाबंदी लगा दी गई।
- >> कूड़ा डोर टू डोर कलेक्शन व्यवस्था से उठाया जाए, न कि जलाया जाए।
- >> लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों के फोन नंबर सार्वजनिक किए जाएं, नागरिक उनसे तत्काल संपर्क कर सकें।
- >> शहर के किसी हिस्से में कचरा जलाया जाए तो नागरिक इन अधिकारियों को सूचित करें, अधिकारी अपने दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करें।
- >> ऑस्ट्रेलिया और लंदन में भी प्रदूषण के हालात बने थे, वहां नियोजित ढंग से हालात सुधारे गए, लखनऊ के लिए भी सरकार और क्षेत्रीय निकाय उन सुधार कार्यों का अध्ययन कर, जरूरी उपाय लागू करें।

प्रदूषण फैलाने में एलडीए व आवास
विकास सहित 22 बिल्डर्स को नोटिस



लखनऊ। वायु प्रदूषण फैलाने के लिए आवास विकास परिषद और एलडीए सहित शहर के 22 बिल्डर्स को नोटिस यूपीपीसीबी ने नोटिस दिया है। यूपीपीसीबी ने नौ और दस नवंबर को एक सर्वे लखनऊ में कराया। इसके बाद यह नोटिस जारी किए गए। यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. रामकरन ने बताया कि सभी बिल्डर्स को जवाब देने के साथ मौके पर निर्माण सामग्री को ढकने और पानी के छिड़काव करने के लिए कहा गया है। ब्यूरो

इनको दिए गए नोटिस

- >> अजिया बॉटनिका, वृंदावन योजना
- >> सांजर बिल्डर, वृंदावन योजना
- >> कासा वीन एग्जोटिका, वृंदावन योजना
- >> आस्था एंटरप्राइजेज, वृंदावन योजना
- >> गोवर्धन एक्लेव, वृंदावन योजना
- >> कहलो गार्डन सिटी-2, वृंदावन योजना
- >> ड्रेजल होम्स, वृंदावन योजना
- >> एलआईजी भवन, आवास विकास परिषद, वृंदावन योजना
- >> पल्स हॉस्पिटल, सरस्वतीपुरम
- >> लोहिया इंस्टीट्यूट का एकेडमिक ब्लॉक, गोमतीनगर
- >> शालीमार गार्डन बे, घेला, आईआईएम रोड
- >> एल्लिको सिटी, आईआईएम रोड
- >> एल्लिको रेगेलिया, आईआईएम रोड
- >> एल्लिको लक्सा, मोहिबुल्लापुर
- >> सोपान एक्लेव, एलडीए, प्रियदर्शिनी योजना
- >> एलएंडटी कंस्ट्रक्शन, गोमतीनगर विस्तार
- >> एनसीसी लिमिटेड, शान ए अवध, सीजी सिटी
- >> पार्थ अर्थ, गोमतीनगर विस्तार
- >> सूरज बिल्डर्स, सीजी सिटी
- >> रेम्की इंफ्रास्ट्रक्चर, सीजी सिटी

निर्माण
कार्य व
जाम पर
लगे
अंकुश

लखनऊ में इस समय बाहरी इलाकों से लेकर अंदरूनी इलाकों तक में निर्माण चल रहा है। सीजी सिटी में रियल एस्टेट की बहुमंजिला इमारतों से लेकर शान ए अवध, पुलिस हेड क्वार्टर, क्रिकेट स्टेडियम के काम चल रहे हैं। वहीं वृंदावन योजना, राजजीपुरम, गोमतीनगर विस्तार, हरदोई रोड पर भी बड़े लेवल पर काम चल रहे हैं। जेपीएनआईसी व मेट्रो के कामों की वजह से भी रात के समय वायु प्रदूषण की आशंका वैज्ञानिक जता रहे हैं। सबसे बड़ा संकट पुराने लखनऊ में चल रहे अवैध निर्माणों से भी है। यहां निर्माण के समय मिट्टी, सीमेंट और मौरंग के कणों के हवा में घुलने से रोकने के लिए प्रयास नहीं किए जाते। खुले में ही निर्माण सामग्री डाली गई है। वहीं सड़कों की क्षमता से अधिक हो चुके वाहन दिन भर जाम का कारण बनते हैं।

Published in:

Amar Ujala, Page no. 5

CSIR-CBRI

15th November 2017

सीबीआरआई ने स्वच्छता पखवाड़े में दिया क्लीन इंडिया का संदेश

साफ-सफाई रखने की शपथ ली, रैली निकालकर किया जागरूक, परिसर में चलाया गया सफाई अभियान

अमर उजाला ब्यूरो
रुड़की।

केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वच्छता शपथ के साथ किया गया। जिसमें निदेशक डा. एन. गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में संस्थान के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वच्छ एवं विकसित भारत के लिए अपने परिवार, मुहल्ले, गांव और कार्य स्थल को साफ रखने में स्वयं भी श्रमदान करने का संकल्प लेकर क्लीन इंडिया का संदेश दिया। इस दौरान

मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सुवीर सिंह ने प्रत्येक दिन विस्तृत कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल बोर्ड, पोस्टर, बैनर्स व स्वच्छता रैली आदि द्वारा स्वच्छता के संदेश का प्रसार किया गया। इस दौरान स्वच्छ परिसर के अंतर्गत संस्थान और आवासीय क्षेत्रों में फर्श से फर्नीचर तक सभी की सफाई तथा कीट नियंत्रण और फॉर्गिंगकी गई। स्वच्छ अनुभागके अंतर्गत सभी अनुभागों में पुराने एवं अप्रयुक्त फर्नीचर, फाइलों, पेपरों, समाचार पत्रों, मैगजीनों आदि को

व्यवस्थित किया गया। स्वच्छ नीलामी के अंतर्गत अप्रचलित और अनुपयोगी वस्तुओं को नीलाम किया गया। स्वच्छ नीर कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान, आवास, स्कूल और अस्पताल में पेयजल फिल्टर, नल, टैंक आदि सभी जल अधिष्ठापनों तथा स्वच्छ प्रसाधन के अंतर्गत सभी शौचालयों, सीवर लाइन, जल निकासी प्रणाली का गहन निरीक्षण और सफाई की गई। स्वच्छ आहार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यालय के कैटीन में स्वच्छ और पौष्टिक आहार, प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध और कूड़ेदान के उपयोग पर जोर दिया गया। साथ ही संस्थान



सीबीआरआई में आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के तहत पौधा रोपण करते संस्थान के निदेशक डा.एन गोपालकृष्णन व अन्य।

के विनीत सैनी के संयोजन में स्वच्छता विषय पर एक निबंध स्वच्छ संवाद के अंतर्गत संस्थान के प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। डॉ. अतुल अग्रवाल ने बताया

कि इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज 15 नवम्बर को संस्थान में विभिन्न स्कूलों के कक्षा कक्षा नौ और दस के विद्यार्थियों के लिए स्वच्छता और आरोग्यता विषय पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर निदेशक डॉ. एन. गोपालकृष्णन एवं अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

कार्यक्रम में रश्मी देवी, प्रशासनिक अधिकारी विनोद कुमार, वित्त अधिकारी जेके चौरसिया, विनीत सैनी, के अरोरा, अर्चना, बीएम सुमन, सोहराब खान, पालक गोयल, मेहराजुदीन आदि मौजूद रहे।

Published in:

Amar Ujala, Page no. 6

Also published in:

Dainik Jagran, Page no.7 , Hindustan, Page no. 4

Utranchal Deep, Page no. 5, Rastriya Sahara, Page no. 9

CSIR-NBRI, CIMAP, CDRI

14th November 2017

500 herbs to contain diabetes found

PNS ■ NEW DELHI

There's good news for diabetic patients looking for herbal remedies for both preventive and therapeutic purposes! Four prominent laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) under the Union Science and Technology Ministry have identified at least 500 herbs that have the efficacy to contain diabetes which is on the rise in the country.

The CSIR labs — National Botanical Research Institute (NBRI), Lucknow, Institute of Himalayan Bio-resource Technology (IHBT), Palampur, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants (CIMAP), Lucknow and Central Drug Research Institute (CDRI), also at Lucknow - have joined hands to prepare formulations from these herbs to tackle the 'silent killer disease'.

Sanjay Kumar, Director of IHBT, Palampur, pointed out that efforts are on to use medicinal properties of various herbs, the exact mixture based on



FOUR CSIR LABS — NBRI, IHBT, CIMAP, CDRI, — HAVE JOINED HANDS TO PREPARE FORMULATIONS FROM THESE HERBS TO TACKLE THE SILENT KILLER DISEASE

knowledge passed down through the generations by traditional healers and ayurveda texts to treat various diseases.

Kumar said the herbal drugs will be scientifically validated before they are launched in market.

"The recent scientifically proven herbal drugs from the CSIR stable has been the first anti-diabetes herbal product 'BGR-34', a combination of natural plant extracts which is finding good response in treatment of Type-2 Diabetes Mellitus," added ex-senior scientist from NBRI, AKS Rawat.

In fact, the anti-diabetic drug which has been developed by the CSIR-NBRI and marketed by pharma firm AIMIL

India has been adjudged as 20th best medicine out of 6,414 drugs of different brands by the All India Organisation of Chemists and Druggists (AIOCD) recently. The BGR-34 is made from the extracts of four plants mentioned in Ayurveda after an extensive research by NBRI and CIMAP scientists to treat diabetes.

India ranks among the top 3 countries with a large diabetic population, according to a 2016 Lancet study. The number of cases stands at 6.45 crore in India in 2014 and is already on rise at an alarming level due to various reasons including sedentary lifestyle.

"Similarly, there have been several groups of herbs such as

ashwagandha, ginseng and rhodiola which, if developed/integrated scientifically has the ability to regulate and manage various diseases. Health issues like asthma, allergy, gynecological ailments, arthritis and gastric problems too have found answers in ayurveda. The CSIR labs will work in tandem to develop the cost-effective ayurveda drugs in a mission mode," added Kumar.

The IHBT Director said that "rising drug resistance, partly caused by misuse of medicines, has rendered several antibiotics and other life-saving drugs ineffective. So there is has been greater need for traditional medicine."

Doctors too admit that alternative medicines in some cases often seems to do a better job of making patients well and at a much lower cost than mainstream care. India's herbal industry is worth about ₹4,200 crore with a potential to reach ₹7,000 crore by 2020 and export of ayurvedic drugs and allied herbal products is about ₹440 crore, according to the Confederation of Indian Industry (CII).

Published in:

The Pioneer, Page no. 5

Also published in:

The Asian Age, Page no. 14

[DNA](#), [Millenium Post](#)

Produced by Unit for Science Dissemination, CSIR, Anusandhan Bhawan, 2 Rafi Marg, New Delhi

CSIR-NBRI

14th November 2017

बढ़ रही है आयुर्वेदिक दवाओं की उपयोगिता



■ सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली।

देश में आयुष दवाओं की उपेक्षा होती है लेकिन यदि आयुष दवाओं को आधुनिक चिकित्सा मानकों की कसौटी पर परखा जाए तो ये दवाएं एलोपैथी से कम नहीं हैं। घरेलू दवा बाजार पर शोध करने वाले फार्मास्युटिक मार्केट रिसर्च आर्गनाइजेशन (एआईओसीडी) का कहना है कि हर्बल दवाओं की उपयोगिता, प्रभावकारिता और मांग बढ़ रही है। दूसरे, इन दवाओं के निर्माण और विपणन प्रक्रिया भी पहले से बेहतर और योजनाबद्ध हुई है।

एआईओसीडी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो सालों के भीतर बाजार में आने वाले 6414 दवा ब्रांडों में से टॉप-20 में स्थान पाने वाली दवाओं में सीएसआईआर विकसित मधुमेह रोधी दवा बीजीआर-34 भी शामिल है। इसे 20वां स्थान मिला है। लेकिन इन 20 दवा फार्मूलों को बीमारियों के इलाज के हिसाब से देखें तो टॉप पांच ब्रांडों में से चार मधुमेह के हैं जिनमें बीजीआर-34 भी शामिल है। इस प्रकार बीते दो सालों में बाजार में छानि वाली मधुमेह की चार दवाओं में से एक दवा आयुर्वेद के सिद्धान्तों पर आधारित है।

दवा को विकसित करने वाली सीएसआईआर की प्रयोगशाला नेशनल बॉटनीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनबीआरआई) लखनऊ के वैज्ञानिक डा. एकेएस रावत ने कहा कि बीजीआर-34 को

सीएसआईआर की मधुमेह की आयुर्वेदिक दवा को टॉप 20 में स्थान मिला, बाकी दवाएं एलोपैथी की

आयुष दवाओं को आधुनिक चिकित्सा मानकों की कसौटी पर परखा जाए तो ये दवाएं एलोपैथी से कम नहीं

यह स्थान इसलिए हासिल हुआ क्योंकि यह एनबीआरआई-सीमैप के वैज्ञानिकों के गहन शोध के बाद बनी है। बाजार में लाने से पहले मनुष्यों पर इसके परीक्षण हुए हैं। इसमें इसकी प्रभावकारिता को परखा गया है। तीसरे, जिस कंपनी एमिल फार्मास्युटिकल को तकनीक हस्तांतरित की गई है, वह दवा के निर्माण में उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन कर रही है।

पिछले दिनों एआईओसीडी ने इस दवा को पुरस्कार प्रदान किया जिसे एमिल फार्मास्युटिकल के कार्यकारी निदेशक संचित शर्मा ने ग्रहण किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि घरेलू दवा उद्योग में व्यापक प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में टॉप 20 दवाओं में आयुर्वेदिक दवा को स्थान मिलना हमारी चिकित्सा पद्धति के लिए गर्व की बात है। उनकी कंपनी इस दवा के विपणन के साथ लोगों में मधुमेह के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शिविरों का भी आयोजन कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है।

Published in:

Rastriya Sahara, Page no. 16

Also published in:

Dainik Jagran, Page no. 7

CSIR-CRRI

12th November 2017

POLLUTION Inclusion of two-wheelers in odd-even scheme would've added 3.3 million extra passengers on road, added to chaos



Sweta Goswami
swetagoswami@htlive.com

NEW DELHI: Delhi transport minister Kailash Gahlot's acknowledgement on Saturday that the existing bus system would not be able cope with the extra 3.3-million passenger load of two-wheeler riders should come as a wake-up call, experts said.

Though the National Green Tribunal gave its nod to the odd-even scheme, but without exemptions to two-wheeler riders and women, the Delhi government on Saturday put on hold the car rationing plan as it felt including bikes and scooters in the scheme would lead to chaos.

The conditional approval of the green court caught the Kejriwal government off-guard, compelling the CM to call an emergency meeting to decide if going ahead with the scheme with no exemptions was possible.

Sources said, in the meeting, Kejriwal was informed that conducting the drive as per the new directive would be "impossible" as even the 500 buses promised by DTC under the Paryavaran Bus Seva had not arrived till Saturday. "The same issue had come up in the previous two odd-even drives. The government has not been able to buy buses due to administrative issues. At the same time, thousands of crores are spent on metro projects. A

standard floor bus costs ₹45 lakh, whereas a kilometre of Metro line costs ₹450 crore," said Ravindra Kumar, principal scientist, Central Road Research Institute.

Delhi's bus fleet currently stands at 5,425 against the requirement of 11,000, which is mandated by the Delhi High Court. Both the DTC and cluster buses need to have a fleet of 5,500 buses each. At least 769 buses have been added to the cluster bus fleet in the last four years but not a single one has been introduced by the DTC ever since the Commonwealth Games in 2010.

The cabinet in September this year had approved the purchase of 2,000 buses. The transport minister had promised these buses would be pressed into service by March 2018 but it is likely to be delayed as it would take two months to prepare the tender. At least another six months would be needed for the first batch of buses to be rolled out.

If this trend continues, then DTC will cease to exist by 2025. The corporation's own report suggests that 99% buses of its existing fleet will have to be taken off the road in five years. This is because its fleet is ageing as the operational life of a bus is 12 years or 7.5 lakh kilometres, whichever is later. As a result, the daily average bus ridership of DTC has declined from 43.47 lakh in 2013-14 to 28 lakh now.

"Buses are the cheapest form of public transport in terms of investment. It is time the government conducts an audit to find what the problem is," said Anumita Roychowdhury, executive director, CSE.

Published in:

Hindustan Times, Page no. 4